सं0संख्या.–12/प0क0–09–17/2018– 639 (12)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार (भा0प्र0से0)
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–27/07/2018

विषयः– **भारत सरकार की स्वास्थ्य संबंधी वैसी सभी योजनाएं जो BPL लाभुकों को दी जानी है, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा BPL की संकल्पना समाप्त कर दिये जाने के कारण उन योजनाओं का लाभ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार द्वारा तैयार पूर्विक्ता प्राप्त परिवार (Priority House Hold) के सदस्यों को अनुमान्य किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार की स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाओं का लाभ बिहार के BPL लाभुकों को अनुमान्य किया जाना है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा BPL लाभुकों की संकल्पना समाप्त कर दिये जाने के कारण इसे लागू किये जाने में व्यवहारिक कठिनाई हो रही थी। फलतः इसे दृष्टिकोण में रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि BPL लाभुकों की सूची की अनुपलब्धता के कारण योजनाओं के लाभ के लिए **खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, बिहार द्वारा तैयार पूर्विक्ता प्राप्त परिवार (Priority House Hold)** की सूची का प्रयोग किया जाय।

प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(संजय कुमार)
प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः– 639 (12) **पटना, दिनांक** 27/07/2018

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को उनके पत्रांक–348524 दिनांक–16.01.2018 एवं पत्रांक–324528 दिनांक–29.08.2017 के आलोक में भविष्य में बिहार सरकार द्वारा नीतिगत निर्णय लेते हुए यदि BPL लाभुकों संबंधी कोई संकल्पना अनुमान्य की जाती है तो इसकी सूचना यथाशीघ्र स्वास्थ्य विभाग/राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध करायी जाय ताकि उन योजनाओं को BPL लाभुकों को ही दिये जाने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किया जा सके के अनुरोध के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/7/2018
सरकार के प्रधान सचिव।

amit..sec-12//